what are the chances of that system? If not, will the Central Government call for the proposal to study the feasibility of that system?

श्रीमती जयवंती मेहताः मेरी जानकारी के मुताबिक गुजरात के लिए लंदन की किसी कंपनी से कोई मांग आई हो, ऐसी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah. This is a question about Gujarat.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir my question is about foreign participation in power generation.

MR. CHAIRMAN: No. This is a specific question about Gujarat. Question No. 623.

सूखा-प्रवण क्षेत्रों की खेती-योग्य भूमि में बदलना

*623 **श्री रमा शंकर कौशिक† :**

प्रो.रामगोपाल यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूखा- प्रभावित क्षेत्रों को खेती-योग्य भूमि में बदलने की सरकारी योजना कब से क्रियान्वित हुई है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या सफलता मिली है तथा इस योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या बंजर भूमि का विस्तार दिन-प्रतिदिन हो रहा है;

(घ) यदि हां,तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बंजर भूमि के विस्तार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.राजा) : (क) से (ड.) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ड.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को फसलों तथा पशुधन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा इन क्षेत्रों को सूखे से मुक्त करने की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः स्थापित करने के मूल उद्देश्य के साथ वर्ष 1973-74 में शुरू

† सभा में यह प्रश्न श्री रमा शंकर कौशिक द्वारा पूछा गया ।

किया गया था । वर्तमान स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने हेतु (13 राज्यों में 164 जिलों के) 947 खंडों को अभिज्ञात किया गया है ।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम को मरुस्थलीकरण के विपरीत प्रभावों तथा फसलों, मानव और पशुधन पर पड़ने वाले विपरीत जलवायु स्थितियों के प्रभावों को कम करने,क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः कायम और दीर्घकाल में मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1977-78 में आरंभ किया गया था । वर्तमान स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने हेतु (7 राज्यों में 40 जिलों के) 227 खंडों को अभिज्ञात किया गया है ।

31.3.1995 तक इन दो क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के समनुरूप विभागों द्वारा क्षेत्रक आधार पर अर्थात् भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास,वनीकरण तथा चरागाह विकास आदि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा था । तथापि, 1.4.1995 से इन कार्यक्रमों को भूमि उपयोग की क्षमता के अनुसार क्षेत्रों के लिए वाटरशेड पद्धति को लागू करके वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है ।

अभी तक इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 3700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.3.1995 तक वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार रहीं थीः-

(लाख हैक्टेयर में)

	सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (लाख हैक्टेयर में)
भूमि संसाधन विकास	29.85	1.71
जल संसाधन विकास	9.46	0.68
वनीकरण तथा चरागाह विकास	17.83	2.76
योग :	57.14	5.15

तत्पश्चात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 41.67 हेक्टेयर क्षेत्र को शमिल करते हुए 8335 वाटरशेड परियोजनाएं तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 3694 वाटरशेड परियोजनाएं आरंभ की गई हैं । 10.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करते हुए (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की) लगभग 2101 वाटरशेड परियोजनाएं तथा 11.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए (मरुभूमि विकास कार्यक्रम की) लगभग 389 वाटरशेड परियोजनाएं पूरी हो गई हैं / पूरी होने वाली हैं ।

जबकि दो क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास के लिए शामिल किए गए क्षेत्रों में अच्छे परिणाम दिखाई दिए हैं तथापि किसी वैज्ञानिक अध्ययन के न होने पर निश्चित तौर पर यह

कहना कठिन है कि राष्ट्रीय स्तर पर बंजर भूमि में बढोतरी हुई है या कमी हुई है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा बंजरभूमि के अलग-अलग अनुमान लगाए गए हैं। बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों के तहत क्षेत्र की मात्रा को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक सुव्यवस्थित सर्वेक्षण करने हेतु हाल ही में कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेन्सी (एन.आर.एस.ए.), अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित किए गए "वैस्टलैण्ड एटलस आफ इंडिया" (मार्च, 2000) से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में बंजरभूमि कुल क्षेत्रफल लगभग 63.85 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया है।

भूमि कटाव और भूमि अवक्रमण अन्य बातों के साथ-साथ दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों, मृदा तथा जल के उपयुक्त प्रबंधन के न होने के कारण भूमि की उर्वरता का ह्रास होने, प्राकृतिक तथा पर्यावरण संबंधी कारणों आदि से होता है। जिसके परिणामस्वरूप भूमि बंजर होती है। मुख्य कार्यक्रम/योजनाओं, (जिसमें भूमि के अवक्रमण को रोककर ऐसी समस्याग्रस्त भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने तथा ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग योग्य बनाने संबंधी कार्य शामिल हैं), जिन्हें इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है, का विवरण नीचे दिया गया है:-

विभिन्न प्रकार की बंजरभूमि को विकसित करने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं।

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)

(i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम।

(ii) प्रोद्योगिकी विकास,विस्तार एवं प्रशिक्षण।

(iii) निवेश संवर्धन योजना।

(iv) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(v) मरूभूमि विकास कार्यक्रम।

2. **कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)**

(i) नदी घाटी परियोजनाओं के तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण, क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु भू-संरक्षण।

(ii) क्षारीय भूमि का सुधार।

(iii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना।

(iv) पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं।

3. **जल संसाधन मंत्रालय**

(i) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जलाक्रांत क्षेत्रों का विकास।

4. **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

(i) समेकित वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना

(ii) क्षेत्रोन्मुखी जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजनाएं।

(iii) वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान योजना।

Changing Drought prone Areas into cultivabel Land

†623. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK:††
PROF. RAM GOPALYADAV:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state

(a) the date since when Government scheme to change drought affected
areas into cultivable land was implemented;

(b) the details of success achieved in this regard and the total amount spent on the scheme till now;

(c) whether the area of wasteland is expanding day by day;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the steps being taken by Government to control the wasteland expansion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI A. RAJA) (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) to (e)The Drought Prone Areas Programme (DPAP) was launched in 1973-74 with the basic objective of minimising the adverse effects of drought on crops and livestock and to rejuvenable the natural resource base of the areas concerned with a view to drought proofing these areas. As of now 947 Blocks (of 164 Districts in 13 States) are identified for coverage under this programme.

The Desert Development Programme (DDP) was started in 1977-78 with the objective of mitigating the adverse effects of desertification and adverse climative conditions on crops, human and livestock populations, to restore the ecological balance of the areas and to control desertification in the long run. As of now, 227 Blocks (of 40 Districts in 7 States) are identified for coverage under this programme.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rama Shanker Kaushik.

These two area development programmes were implemented on a sectoral basis *i.e.* for Land Resource Development Water Resource Development, Afforestation and Pasture Development etc. by the line departments of the State Governments upto 31-3-1995. However, with effect from 1-4-1995 the programmes are being implemented, on aWatershed basis, involving Watershed treatment of the areas in accordance with the land use capability.

So far, a sum of about Rs. 3700 crores has been spent under the two programmes. The physical achievements upto 31-3-1995 under these programmes were as under:—

(in lakh hectares)

	DPAP	DDP
Land Resource Development	29.85	1.71
Water Resource Development	9.46	0.68
Afforestation and Pasture Development	17.83	2.76
TOTAL:	57.14	5.15

Thereafter 8335 watershed projects covering an area on 41.67 lac hectares under DPAP and 3694 watershed projects covering 18.47 lac hectares under DDP have been taken up. An estimated 2101 watershed projects (of DPAP) covering an area of 10.50 lac hectares and 389 watershed projects (of DDP) covering an area of 11.95 lac hectares are completed/nearing completion.

While the areas taken up for development under the two area development programmes have shown good results, it is difficult to say for certain that, at the national level, the wasteland is increasing or decreasing in the absence of any scientific study. There have been varying estimates of Wastelands by different agencies. Steps have recently been initiated to conduct a systematic survey, on a scientific basis, for the quantification of different categories of Wasteland. Data now made available from the "Wasteland Atlas of India" (March, 2000), brought out by the National Remote Sensing Agency (NRSA). Department of Space, Hyderabad, estimated the total extent of Wastelands in the country at about 63.85 million hectares.

The process of soil erosion and land degradation, which results in Wastelands occurs, *inter alia,* on account of faulty cultivation practices, deterioration owing to lack of appropriate soil and water management, and natural and environment causes. The main Programmes Schemes (having components to develop/reclain such problem lands by checking land

degradation and putting lands into productive use), which are currently being implemented, are shown here under:

Main Programmes/Schemes being implemented for the development of various types of Wastelands

1. Ministry of Rural Development (Department of Land Resources)

(i) Integrated Wastelands Development Programmes (IWDP)
(ii) Technology Development, Extension and Training (TDET)
(iii) Investment Promotional Scheme (IPS)
(iv) Drought Prone Areas Programme (DPAP)
(v) Desert Development Programme (DDP)

2. Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation)

(i) Soil conservation for enhancing the productivity of degraded lands- in the catchments of River Valley Projects (RVPs) and Flood Prone Rivers (FPR)
(ii) Reclamation of Alkali Soil (RAS)
(iii) National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA)
(iv) Watershed Development Projects for Shifting Cultivation Areas (WDPSCA) in the North Eastern States.

3. Ministry of Water Resources

(i) Reclamation of Waterlogged Areas under the Command Area Development Programme (CADP)

4. Ministry of Environment and Forests

(i) Integrated Afforestation and Eco Development Project (IAEP)
(ii) Area Oriented Fuel wood and Fodder Projects (AOFFP)
(iii) Grant-in-Aid Scheme for Afforestation and Tree Planning.

श्री रमा शंकर कौशिकः सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी से जहां मैंने केवल सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कृषी योग्य भूमि को ठीक करने का सवाल पूछा था वहां उन्होंने मरूस्थल की नई बात जोड़ी है उसकी भी पूरी सूचना नहीं दी है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 947 विकास खंडों को चिन्हित किया गया है, अभिज्ञात किया गया है। वहां सूखे की

वजह से खेती बंजर होती जा रही है । 247 विकास खंड ऐसे हैं जिनमें मरुस्थल की वजह से भूमि बंजर और खराब होती जा रही है, वहां खेती नही हो रही है । आश्चर्यजनक और खेदजनक बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने इस योजना में अब तक 3700 करोड़ रुपये खर्च कर दिए लेकिन उपलब्धि क्या रही ? कितनी बंजर भूमि थी ? बंजर भूमि में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, इसकी सूचना मंत्री जी ने नहीं दी है । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि 1973-74 में जब यह योजना शुरू की गई थी तब हमारी सरकार का अनुमान क्या था ? कितनी भूमि बंजर हो चुकि थी तथा उसे सुधारने की कितनी आवश्यकता है ?

SHRI A. RAJA: Sir, so far as the reclamation of lands in drought-hit areas in concerned, it is not a programme which is exclusively done by my Ministry alone. Some other Ministries, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Environment and Forests, are also involved in it. So far as the drought areas are concerned, we are implementing three major schemes, namely, the Drought-Prone Area Programme (DPAP), the Desert Development Programme (DDP) and the Intergrated Wasteland Development Progamme (I WDP). As far as the motto and objective of these programmes in concerned, it is to reclaim the wastelands in non-forest areas by checking and degradation and putting such •lands to sustainable use, and*thereby increase the bio-mass production, especially fuelwood and fodder.

The hon. Member has put a question about the total coverage and the percentage of coverage. Sir, I think, for the first time in the year 1999-2000, during last March, a survey was conducted with the help of Indian Space Research Organisation (ISRO), a remote sensing agency at Hyderabad. This is the first time that this survey has been conducted. Some figures have been sent by ISRO. So far as other coverage is concerned, we have to conduct a study with other Departments as to what achievements have been made by them. Then they will be clubbed. Again, after five years, another surve would be conducted. Then only we can compare the achievements in a strict manner. At present, we have conducted this survey for the first time. Keeping in view the figures sent by ISRO, we are trying to improve the situation.

श्री रमा शंकर कौशिकः श्रीमन, मेरे प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं आया । लेकिन माननीय मंत्री जी ने सूचना दी । यह बात सही है कि उन्होंने कुछ योजनायें शुरू की हैं । ये 1973-74 से 1995 की हैं वह उन्होंने लगभग 50 लाख हेक्टेयर में की हैं और अब उस योजना में 41 लाख हेक्टेयर का इजाफा किया है । लेकिन प्रश्न मूल रूप से यह नहीं है । पैसे का खर्चा तो इस योजनाओं में हुआ ही है यह बात सही है । लेकिन प्रश्न यह है हमारी खेती पर इसका असर बहुत ही विकराल रूप से पड़

रहा है । हमारी खेती कम होती जा रही है । जहां 80 के दशक में हम अपने अनाज की पैदावार में बढोत्तरी कर रहे थे, 37 फीसदी का बढोत्तरी हम कर रहे थे वहां अब यह बढोत्तरी केवल 12 प्रतिशत रह गई है । दूसरे बहुत से कारण हैं लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारी बंजर भूमि बढ़ती जा रही है । सूखा प्रभावित होने की वजह से,जल संसाधनों के न होने के कारण, जल न रोकने के कारण से बंजर भूमि बढ़ती जा रही है । श्रीमन् , एक एजेंसी के अनुसार 10-15 साल पहले हमारी 550 हेक्टेयर भूमि बंजर थी जो आज 750 लाख हेक्टेयर हो गई है और जो हमारी अनाज की स्थिति है वह भी घटती जा रही है । हमारी बंजर भूमि भी बढ़ रही है और पैसा भी खर्च हो रहा है । यह बात सही है कि इस पर 37 सौ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन फिर भी बंजर भूमि बढ़ती चली जा रही है । यह एक विचित्र स्थिति है, एक विचित्र संयोग है कि पैसा भी खर्च हो,योजनायें भी चलें और बंजर भूमि भी बढ़ती रहे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालय इस काम को देखते हैं मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे- क्योंकि यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है 947 विकास खंड है और यदि इन विकास खंडों में आप अपना सर्वे नहीं कर सकते और केवल हवाई सर्वे के भरोसे बैठे रहेंगे या कोई ठीक वैज्ञानिक दृष्टि न होने के कारण नहीं कर पायेंगे तो यह एक अजीब-सी बात होगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपकी विभिन्न योजनायें हैं क्या उनके लिए किसी एक विभाग को या किसी एक मंत्रालय को आप जिम्मेदार बनायेंगे और उसका पूरी तरह से सर्वे कराकर सदन को सूचना देंगे कि कितनी बंजर भूमि हमारी ठीक हो रही है ?

SHRI A. RAJA: Sir, I should honestly admit that we cannot fix up the exact ratio and the exact coverage of the wasteland, which has been covered by this Ministry or by that Ministry. We are making out best efforts to cover it. It is a long-term process and will take at least five years. When a watershed project is sanctioned to a State or to a block, it has to work for five years. Then only we can make an assessment. Another thing is this. If at all any watershed project completes five years, we cannot say that it will be kept alive or it will be kept under green courage after ten years. There is every chance that it can be reverted back to drought-hit areas due to natural calamities and other things. So, this coverage aspect, i.e. fixing up of the exact vegetative coverage, of the wasteland development, degradation of land, is not a fixed one. it fluctuates now and then. In spite of that, I assure the house that we will look into the matter. We will also try to prolong the so- called schemes which have been contemplated by the Ministry in a perpetual manner.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I have to put two-question to the hon. Minister, (a) Whether the Minister w^ll be able to give, now or afterwards, the names of the districts and blocks which have been identified, *i.e.* 947 blocks in

164 districts where the schemes are being implemented and the results so far. Sir, a lot of money is being spent on these schemes but the result that is achieved is not satisfactory at all. That being the case, will the Minister consider associating the Members of Parliament with these programmes, *i.e.* DPAP, the Desert Development Programme and the Watershed Management Programme. If that area falls in the jurisdiction of a particular constituency, will you consult the Member of that constituency? Will the Government consider associating the Members of Parliament with these programmes so that they can play the role of an advisor or a supervisor in regard to these projects?

SHRI A. RAJA: Sir, at present, we are not maintaining any district-wise list. But we are having a State-wise list. As to how many projects under the DPAP, the DDP and IWDP were taken up and are being worked out, I will supply this list to the hon. Member. So far as his question regarding consultation with the Members of Parliament is concerned, Sir, when we sanction a watershed programme under the Wasteland Development Programme, we consult the DRDAs and the Gram Sabhas. All the NGOs working in that area and notable and eminent persons are also included in the Committee. They make a plan in a proper manner. In spite of that, if the hon. Member wants that we should consult the Members of Parliament, we will consider this proposal and we will try to sort out a plan in consultation with the Members of Parliament.

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, if we analyse the kind of investment that has been made in terms of the Wasteland Development Programmes, we find that there is a scheme where the private sector is supposed to take up projects under the Wasteland Development Programmes. There is hundred per cent freedom to the private sector. For continuously three years, the project is there and the allocation is there but there are not takers. What is the situation; why can't these schemes be made more effective? We hear day in and day out that there should be so much constribution from the private investors. What is the feedback from the CH, the FICCI and ASSOCHAM with which the Government interacts quite regularly? There was some initiative taken to have some discussions with Israel. They have developed some technology. According to their assessment many of the so-called desert development areas are actually areas where we can have greenery and fertility. What is the result of that process which had been initiated earlier?

SHRI A. RAJA: Sir, so far as participation of the private sector is concerned, we are having a scheme in the name of Investment Promotional Scheme. Of course, there is very little budget for this scheme. The budget is

course, there is very little budget for this scheme. The budget is Rs. 50 lakhs. Sir, apart from the Government machinery, nine Departments of the Government are involved in the Watershed Management Programmes. The problem on the part of the fanners is, they should have at leat 50 acres of land. We are giving 25 per cent subsidy for this purpose. Probably, the reason for decreasing the budget outlay is, there is no proposal at all before the Ministry to sanction the amount. This year we will consider the budget outlay. If more proposals emerge from the private sector, we will consider them in due course of time.

SHRI NILOTPAL BASU: What is the result of your interaction with them? Why aren't they investing money?

SHRI A. RAJA: Where do you want? There is no proposal at all.

SHRI NILOTPAL BASU: You are continuously interacting with them. The Government is continuously interacting with them. Every day we see the Finance Minister or the External Affairs Minister or the Prime Minister interacting with the trade associations and the industry associations. What is their feeback? Why aren't they forthcoming? This is a very vital programme. What is your feedback?

SHRI A RAJA: Sir, no proposal are coming.

SHRI NILOTPAL BASU: But you are discussing with them.

SHRI A. RAJA: When there are no proposal from the private sector, we canot offer them anything. The Ministry has formulated certain guidelines. These guidelines are available to them. It is open to all to file a project. Subject to its feasibility, we are ready to sanction it.

श्री मूल चन्द मीणा : चेयरमैन सर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 3700 करोड़ रुपया 1995 तक खर्च किया है । सूखाबहुल क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 57.14 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर सुधार किया गया है और मरुभूमि विकास कार्यक्रम में 5.15 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनायी गयी है । मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि 1995 और 2000 के पीरियड के बीच में कितनी भूमि आपने कृषि योग्य बनायी और उस पर कितना पैसा खर्च किया ? साथ ही आपने वाटरशेड बात की । चेयरमैन सर, मरुभूमि और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्यक्रम में राजस्थान एक बहुत बड़ा एरिया है । यह जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें बहुत कड़ा करप्शन होता है । उस करप्शन को रोकने के लिए और आपने जो वाटरशेड की बात है तो क्या इनका मूल्यांकन कराया है ? जो पैसा खर्च किया गया है कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए क्या उसका कोई मूल्यांकन कराया गया है या कोई समीक्षा की गयी है ? समीक्षा नहीं की गयी है या समीक्षा करने का कोई तरीका है, यह स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

SHRI A. RAJA: Sir, from 1995-96 to 1999-2000, usually this is one integrated period for watershed development — the total number of watershed development projects sanctioned under DPAP were 8,335 and the area covered was 41.67 lakh hectares; and the number of watershed projects sanctioned under DDP were 3,694 and the area covered was 8.02 lakh hectares. As regards the issue of corruption which has been mentioned by the hon. Member, till this date, no allegation or any petition has been received by this Ministry. If there is any allegation made in writing, and if that is brought to my notice, then, I will consider it.

SHRI VEN DHAMMA VIRIYO: I want to put one question to Hon. Minister. A lot of money has been allocated for protection from Banjar bhoomi. Apart from the money that has been sanctioned, can you kindly tell me what is the system that you have evolved to protect them? Money alone is not enough. What process you have undertaken in this scheme?

SHRI A. RAJA: As I have mentioned earlier, we are implementing three major schemes. And we are exercising stringent measures for the success of these schemes. So far as his State is concerned, if he offers any suggestions, then we can consider them.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I would like lo know which are the drought affected areas identified in Tamil Nadu for the purpose of converting them into cultivable lands and how much money has been sanctioned. My second supplementary is this. What is the extent of the wasteland identified in Tamil Nadu? My third supplementary is, the Minister had stated that no proposal has come from anywhere. As a matter of fact, about two years back, I had given a proposal, and the then Minister, Shri Yerran Naidu recommended that proposal, but nothing has come out of it and there is also no intimation about what happened to that proposal. I would like the hon. Minister to enlighten me on this matter.

SHRI A. RAJA: Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, under DPAP, 699 projects have been taken up. As the House is well aware, one project covers 50 hectares and, for each hectare, we are spending Rs. 4,000 under the DPAP; if it is under DDP, we spend Rs. 5,000 per hectare. So, 699 projects have been sanctioned under DPAP in Tamil Nadu. Under Integrated Wasteland Development Programme eleven programmes were launched. As far as the financial position is concerned, Rs. 827 lakhs has been sanctioned for Tamil

Nadu under DPAP and Integrated Wastelnd Development Programme; Rs. 484.93 Lakhs has been given to Tamil Nadu. It has been alledged by the hon. Member that he has submitted a proposal and it has not been looked into so far. We will give the full details. I will enquire into the matter and give the full details later.

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर : आनरेबल चेयरमैन साहब,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि देश में जो 550 लाख हेक्टेयर की बजाय अब 750 लाख हेक्टेयर रकबा बैरन लैंड हो गया है, और 3700 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया है, जबकि पंजाब में पठानकोट से लेकर रोपड़ तक,एक-एक हजार फीट की गहराई तक मुश्किल से पीने के लिए पानी उपलब्ध है, तो क्या पंजाब में भी इस रकम से कोई प्रोजैक्ट मंजूर किया गया है ? अगर हां, तो कितनी रकम दी गई है और उसके क्या असर पड़े हैं ?

SHRI A. RAJA: Sir, as the House is aware, Punjab is a State which has not been hit by drought so severely. As such, we have given 7.70 lakhs so far under this scheme.

624. [The Questioner (Shri K.M. Khan) was absent. For Answer *vide* page 29 *infra]*

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

625.**श्री गोपाल सिंह जी. सौलंकी :**क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए देश में विद्युत उत्पादन का कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।